Reported Shifting of Patna BHEL office to Durgapur in West Bengal

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार)ः महोदय, पटना में पावर प्लांट से संबंधित BHEL की एक इकाई है, लेकिन उसको वहां से शिफ्ट करके दुर्गापुर ले लाया जा रहा है।

महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बरौनी और कांटी थर्मल पावर स्टेशन हैं, वहां अभी 800 करोड़ रुपये की लागत से उनके रेनोवेशन का काम चल रहा है। क्या तुक है कि इसी बीच में इस पावर प्लांट यूनिट को पटना से उठा करके दुर्गापुर ले जाया जाए। यह क्या साजिश है? क्या आप चाहते हैं कि बिहार में आज जो बिजली का संकट है, बिजली की scarcity है, उसको और भी गहरा बना दिया जाए? हर स्टेट में इस तरह का एक सर्विस सेंटर होता है। बंगाल में ऑलरेडी एक सैंटर है। दुर्गापुर को आप एक और सर्विस सैंटर देना चाहते हैं, तो दे दीजिए, हम लोगों को कोई एतराज नही हैं, लेकिन बिहार से उठा करके आप उस सर्विस सेंटर को क्यों वहां पर ले जा रहे हैं?

महोदय, इसके कारण पटना में आंदोलन हो रहा है। कांटी, मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार में इसके लिए आंदोलन हो रहा है। लोग धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक उकसाने वाली बात है क्योंकि पहले से वहां पर विकास का काम हो रहा है और बहुत मुश्किल से वह एक ट्रैक पर आया, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली। भारत सरकार आखिर क्या चाहती है? वह क्यों वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा करना चाहती है? अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे इम्प्लॉइमेंट के जो ऐवीन्यूज बनते हैं, उन पर भी इसका असर पड़ने वाला है और जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उस पर भी इसका एडवर्स इफैक्ट पड़ेगा।

महोदय, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस तरह की हरकत से बाज आए, वरना हम लोग इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से मंत्री महोदय जवाब दें और इस सदन को आश्वासन दें कि वह ऐसा काम नहीं करेंगे और उसे वहां से उठा करके शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : महोदय, मैं इनका समर्थन करता हूं। इस पर मंत्री महोदय से जवाब दिलाया जाए।

श्री एन.के. सिंह (बिहार) : महोदय, मैं भी इनका समर्थन करता हूं।

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार) : महोदय, मैं भी इनका समर्थन करता हूं।

Regional imbalance in the distribution of natural gas

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I would like to draw the attention of this august House to the fact that the Government of India has gone on record rightly in asserting that the country's natural gas reserves including the gas of KG Basin is a national asset and the interest of the national economy cannot be held hostage to the benevolence and mercy of some private players. This had been widely reported in the media yesterday. 1 highly appreciate, and welcome such firm assertion by the Government of India and also by the hon. Minister who is sitting over here. Such a firm assertion, if we have to remain consistent with, needs urgent action in the matter of a proper, transparent and rational pricing and, at the same time, a proper distribution mechanism under the control of the State. Sir, natural gas is our property; it is